जवाहर लाल गुप्ता और पी. के. जैन से पहले, जे जे।

भारत और एक और पर्यावरण समाज-याचिकाकर्ता

बनाम

प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन और *अन्य-उत्तरदाता*

97 का *सी.* डब्ल्यू. पी. 1721

3आर. डी. जुलाई, 1997

भारत का सह-संस्थान, 1950-कला।51(ए), *226-सार्वजनिक* मुकदमेबाजी-चंडीगढ़ प्रशासन *की कार्रवाई! भूमि आबंटन में।*

मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सेक्टर 21-सी, चंडीगढ़ में एक आधुनिक पेट्रोल पंप *की स्थापना में प्रदूषण, सार्वजनिक खतरे, जनहित के खिलाफ, भारतीय सड़क कांग्रेस के संशोधनों के उल्लंघन, पेट्रोलियम उत्पादों और* विस्फोटक *सबस्टैन। की बिक्री को विनियमित करने वाले प्रावधानों के खिलाफ और इस याचिका* पर *भी चुनौती दी गई* कि *इस क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप मौजूद हैं* और *आरोपों को साबित करने के लिए विशिष्ट दावों की अनुपस्थिति में में कोई और दावा करने की आवश्यकता नहीं है- भूमि आवंटित करने में सरकार के निर्णय को* बरकरार *रखा गया- जनहित में आयोजित सुविधा* की *स्थापना-लिखित याचिका खारिज की गई।*

यह माना गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवंटन एक सरकारी कंपनी को किया गया है, किसी भी निजी लाभ का सुझाव पूरी तरह से निराधार प्रतीत होता है।न ही यह कहा जा सकता है कि यह कार्रवाई राज्य के खजाने के खिलाफ या उसके खिलाफ है।जनहित।जब प्रशासन को विश्वास हो जाता है कि यह सुविधा जनहित में होगी, तो उसकी कार्रवाई को केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भूमि को संभवतः खुली नीलामी में अधिक कीमत मिल सकती थी।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की कार्रवाई की वैधता को एक निजी व्यवसायी के मानकों से नहीं आंका जा सकता है।पहला सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए बाध्य है जबकि दूसरा निजी हित द्वारा निर्देशित है।तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन किसी बाहरी विचार से प्रेरित था या उसने जनहित के खिलाफ काम किया था।

(पैरा 13)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि सुसंगत तथ्यों पर विचार करने पर, सक्षम प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी-निगम को भूमि आवंटित करना उचित समझा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने मध्यस्थता से कार्य किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि सुविधा की स्थापना से प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा।प्रतिवादी की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदूषण तब होता है जब वाहनों को ईंधन प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है।यदि आधुनिक सुविधाओं से भरे हुए राज्य हैं और ईंधन तेजी से भरा जाता है, तो प्रत्येक वाहन को मोड़ की प्रतीक्षा करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।प्रदूषण भी ऐसा ही होगा।

(पारस 16 &17)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बाध्य है।वास्तव में, यह एक दायित्व है जो न केवल राज्य के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए भी लागू होता है।हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रशासन पर्यावरण की रक्षा करने में विफल रहा है।

(पैरा 19)

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि नई सुविधा पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगी।यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि यह किसी भी प्रदूषण का कारण बन सकता है।याचिका में किए गए सामान्य और अस्पष्ट कथन सकारात्मक निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकते हैं।

(पैरा 21)

इसके अलावा यह माना गया कि चंडीगढ़ का आधुनिक शहर समृद्ध रूप से एक आधुनिक सुविधा का हकदार है।इस तरह की सुविधा की स्थापना को रोकने से जनहित को बढ़ावा नहीं मिलेगा।मामले की परिस्थितियों में, प्रतिवादी की ओर से यह सुझाव कि याचिका जनहित में नहीं है, बल्कि एक निजी हित याचिका है, पूरी तरह से निराधार नहीं कहा जा सकता है।हम और नहीं कहते हैं।

(पैरा 27)

जे. एस. नारंग, श्री दीपिंदर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह कामरा, अधिवक्ता, *याचिका। ऑनस*के *लिए।*

हितेंद्र सिंह, अधिवक्ता, *प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए।*

प्रतिवादी संख्या 8 के लिए श्री सलिल सागर, अधिवक्ता और सुश्री रितु कोहली, अधिवक्ता *के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल,9.*

प्रतिवादी की ओर *से अनिल राठी, अधिवक्ता नंबर 6 और 7,10.*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) क्या सेक्टर 21-सी, चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को भूमि आवंटित करने में चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई अवैध है?यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है।कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी हैं।वे पर्यावरण की सुरक्षा में रुचि रखने का दावा करते हैं।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अंचल 21 में समाज के कमजोर खंड रहते हैं।इसमें छोटे-छोटे घर हैं।स्कूटर और कार मरम्मत का बाजार है।ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं किए गए हैं।1 किलोमीटर के दायरे में 10 पेट्रोल पंप हैं। इन तथ्यों के बावजूद, प्रशासन ने प्रतिवादी संख्या 8 और 9 अर्थात भारत पेट्रोलियम निगम को एक और पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार मौजूदा पेट्रोल पंप क्षेत्र के निवासियों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान कर रहा है और नए पेट्रोल पंप की स्थापना से प्रदूषण से बचा जा सकता है।जोनिंग योजना का उल्लंघन करते हुए पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए भूमि को तराशा गया है।इसे बहुत कम दर पर पट्टे पर दिया गया है।इसके परिणामस्वरूप जनता को आर्थिक नुकसान हुआ है।यह भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।यहाँ तक कि प्रेस ने भी विभिन्न रिपोर्टों को प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया

था कि पेट्रोल पंप स्थापित करना जनहित में नहीं था।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिनिधित्व किया था और यहां तक कि प्रतिवादी को नोटिस भी दिए थे।इसके बावजूद, भूमि प्रशासन द्वारा आवंटित की गई है।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह संविधान के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है।पंप की स्थापना से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा।आग लगने का खतरा है।पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं हैं और पेट्रोल पंप की स्थापना एक 'सार्वजनिक खतरा' पैदा करेगी।' याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों और विस्फोटक पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने वाले प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।नतीजतन, याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 8 और 9 को स्थल आवंटित करने के प्रशासन के निर्णय को रद्द कर दिया जाए और भविष्य में भी उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध का एक रिट जारी किया जाए।

(3) प्रतिवादियों ने अपने याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध किया और चंडीगढ़ प्रशासन और उसके अधिकारियों की ओर से बयान दायर किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि याचिका की गणना व्यक्तिगत हित के लिए की गई है न कि सार्वजनिक हित के लिए। भूमि आवंटन का निर्णय जनहित में लिया गया था। निगम एक खुदरा बिक्री केन्द्र उपलब्ध करा रहा है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है जो प्रदूषण को रोकता है। इस रिटेल आउटलेट को उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी।

(4) प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की ओर से एक अलग लिखित बयान भी दायर किया गया है। उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक। यह कहा गया है कि "इस रिट याचिका में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से अन्य पेट्रोल पंपों के मालिकों की ओर से एक अन्य पेट्रोल पंप की स्थापना को रोकने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के अलावा और कुछ नहीं हैं..." याचिका न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यह कहा गया है कि साइट को पेट्रोलियम कानूनों और विस्फोटकों से संबंधित कानूनों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया. भारतीय विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोप विवादास्पद रहे हैं।

(5) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, प्रतिवादी संख्या 8 और 9 की ओर से एक लिखित बयान भी दायर किया गया है। यह बताया गया है कि कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी है। यह सभी सहायक सुविधाओं के साथ पेट्रोल पंप की स्थापना कर रहा है, जिसकी लागत रु. 2.50 से रु. 3.00 करोड़. यह सुविधा कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगी। अब तक, कंपनी ने बॉम्बे में एक और दिल्ली में दो यूनिट स्थापित की हैं। मामले की जांच के बाद प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए 100 से 200 फीट का प्लॉट स्वीकृत किया गया था. विस्फोटक नियंत्रक ने 7 फरवरी, 1997 को मंजूरी दे दी थी। यह सुविधा पर्यावरण के अनुकूल होगी। उत्तरदाताओं ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने सेक्टर 27 और 34 में नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने पर कोई विरोध नहीं जताया था। उन्होंने पंप के कामकाज के खिलाफ कोई विरोध नहीं जताया है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है और वर्ष 1970 से अस्तित्व में है। सुझाव यह है कि याचिका जनहित को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा से बचने के उद्देश्य से दायर की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार या प्रदूषण बोर्ड के समक्ष उपाय की मांग कर सकते थे, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत कार्रवाई

शुरू कर सकते थे यदि यह स्थापित हो जाता कि पेट्रोल पंप प्रदूषण पैदा कर रहा था। . गुण-दोष के आधार पर लगाए गए आरोप विवादास्पद रहे हैं।

(6) याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी की ओर से किए गए दावे को पलटने के लिए एक प्रतिकृति दायर की है।

(7) पार्टियों के वकील को सुना गया है।

(8) याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. एस. नारंग और विद्वान अधिवक्ता श्री दीपिंदर सिंह ने तर्क दिया कि पेट्रोल पंप की स्थापना को मंजूरी देने में प्रतिवादी की कार्रवाई अवैध है क्योंकिः

(i) इससे मौजूदा प्रदूषण बढ़ेगा।चूंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप मौजूद हैं, इसलिए अब और प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) पंप के लिए भूमि बहुत कम दर पर दी गई है जिससे राज्य के पूर्व राजकोष को नुकसान होगा।कार्रवाई आर्थिक रूप से मूर्खतापूर्ण है;

(iii) राज्य अनुच्छेद 48-ए के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है क्योंकि उसने पर्यावरण की रक्षा नहीं की है।

(iv) पंप की स्थापना के लिए चुना गया स्थान भारतीय सड़क कांग्रेस की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है और इसलिए, अवैध है।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि राज्य को सार्वजनिक उद्यानों में पेड़ लगाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का प्रतिवादी के वकील ने किया था।निगम विद्वान अधिवक्ता श्री हीरा लाई सिब्बल ने कहा कि याचिका दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई है।याचिकाकर्ताओं ने *अनुरोध नहीं* किया है कि प्रदूषण पैदा करने वाले पेट्रोल पंपों को इस तथ्य के बावजूद बंद कर दिया जाना चाहिए कि वे नवीनतम मानकों को पूरा नहीं करते हैं।याचिकाकर्ता चाहते हैं कि प्रतिवादी-कंपनी को प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए आधुनिक सुविधा स्थापित करने से रोका जाना चाहिए।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इकाई स्थापित होने पर किसी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनेगी।वास्तव में, कोई प्रदूषण नहीं होगा।भारत संघ के वकील श्री अनिल राठी ने प्रस्तुत किया कि सभी क़ानून या प्रावधानों का पालन किया गया है।प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।यह बताया गया कि भूमि का आवंटन कानून के अनुसार किया गया है।

(10) पार्टियों के वकीलों को सुनने के बाद, जो प्राथमिक सवाल उठता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी ने ईंधन भरने और सेवा स्थिति स्थापित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 8 और 9 को एक स्थान आवंटित करने में अवैध रूप से काम किया है।

अर्थशास्त्रः

(11) सबसे पहले आर्थिक पहलू।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि भूमि प्रतिवादी-निगम को कम कीमत पर दी गई है।प्रशासन ने अपने जवाब में आरोप का खंडन किया है।यह कहा गया है कि साइट को 15 साल की अवधि के लिए मासिक किराए पर पट्टे पर दिया गया है।पहले पाँच वर्षों के लिए रु 96, 707 प्रति माह और 25 प्रतिशत की वृद्धि के

साथ यानी रु। अगले पाँच वर्षों के लिए 1,20,884 प्रति माह और आगे 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अर्थात रु 1,51,105 बाद के वर्षों के लिए प्रति माह।" याचिकाकर्ताओं ने एक प्रतिकृति दायर की है।हालाँकि, लिखित कथन के पैराग्राफ 11 में किए गए उपरोक्त कथनों का विरोध नहीं किया गया है।

(12) उपरोक्त के अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत पेट्रोलियम निगम एक सरकारी कंपनी है।इसने रुपये से लेकर रुपये तक की पर्याप्त राशि का निवेश करने का बीड़ा उठाया है। 2. 50 करोड़ से रु। इस सुविधा की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये।कोई अन्य व्यक्ति या निगम ऐसी इकाई स्थापित करने के लिए आगे नहीं आया है।

(13) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवंटन एक सरकारी कंपनी को किया गया है, किसी भी निजी लाभ का सुझाव पूरी तरह से निराधार प्रतीत होता है।न ही यह कहा जा सकता है कि यह कार्रवाई राज्य के पूर्व राजकोष या सार्वजनिक हित के खिलाफ है।जब प्रशासन को विश्वास हो जाता है कि यह सुविधा जनहित में होगी, तो उसकी कार्रवाई को केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भूमि को संभवतः एक खुली भूमि में अधिक कीमत मिल सकती थी।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की कार्रवाई की वैधता को एक निजी व्यवसायी के मानकों से नहीं आंका जा सकता है।पहला सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए बाध्य है जबकि दूसरा निजी हित द्वारा निर्देशित है।तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन किसी बाहरी विचार से प्रेरित था या उसने जनहित के खिलाफ काम किया था।

पर्यावरणः

(14) याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इस सुविधा की स्थापना से मौजूदा प्रदूषण में वृद्धि होगी।वास्तव में, सुविधा की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

(15) यह सच है कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण में हस्तक्षेप के मनुष्यों के लिए गंभीर परिणाम हैं।प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक ध्यान और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रभावित न हो।इन "मानव प्रकार की स्थायी संपत्तियों" को "समाप्त" नहीं किया जाना चाहिए।यह एक ऐसा काम है जिसे न केवल सरकार बल्कि हर नागरिक को करना है

उपक्रम करें।यह संविधान के अनुच्छेद 51-ए में निहित एक कर्तव्य है।साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि प्रकृति को भी निष्क्रियता पसंद नहीं है।स्थिर जल आम तौर पर जमा हो जाता है।समान रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी हमेशा पर्यावरण का दुश्मन नहीं है।यह सुरक्षा भी हो सकती है।इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रकृति के प्रति सहानुभूति मनुष्य के धर्म का हिस्सा होनी चाहिए।

(16) दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मामले में क्या स्थिति है, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बने घरों में रहने वाले व्यक्ति 250 गज से लेकर 1000 गज तक समाज के कमजोर खंड से संबंधित हैं।एक ऐसे देश में, जहां अधिकांश लोगों के पास मौसम की अनिश्चितताओं से खुद को बचाने के लिए छत नहीं है, याचिकाकर्ताओं की ओर से दिया गया सुझाव पूरी तरह से असमर्थनीय है।समान रूप से, यह सुझाव अस्वीकार्य है कि सुविधा स्थापित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि क्षेत्र में 10 पेट्रोल पंप हैं।खुशी की बात है कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ में चलने वाले वाहनों की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं और विशेष रूप से इस सड़क पर जो एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ हरियाणा की ओर जाने वाला मार्ग है।वे उन वाहनों की कतारों

को भी नजरअंदाज करते हैं जो अक्सर पेट्रोल पंपों पर ईंधन पाने के लिए इंतजार करते हुए देखे जाते हैं।यदि प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने पर, सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी-निगम को भूमि आवंटित करना उचित समझा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने मध्यस्थता का कार्य किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि इस सुविधा की स्थापना से प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा।

(17) याचिकाकर्ताओं का मानना है कि पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ेगा।बिना किसी और चीज के, यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत नहीं होता है यह कहने के समान है कि अगर अधिक डॉक्टर हैं, तो अधिक बीमारियां हो सकती हैं।वास्तव में ऐसा नहीं भी हो सकता है।वर्तमान मामले में, प्रतिवादी की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदूषण तब होता है जब वाहनों को ईंधन प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है।यदि आधुनिक सुविधाओं से भरे हुए स्थान हैं और ईंधन तेजी से भरा जाता है, तो प्रत्येक वाहन को मोड़ की प्रतीक्षा करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।प्रदूषण भी ऐसा ही होगा।वर्तमान मामले में ठीक यही बताया गया है।

(18) इसके अलावा, यह भी उल्लेख करने योग्य है कि जब विभिन्न अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंप लगाए गए थे तो याचिकाकर्ताओं ने अपनी उंगली नहीं उठाई थी।उन्होंने इस तथ्य के बावजूद कि वे पुराने का उपयोग करते हैं, 1 किमी के दायरे में 10 पेट्रोल पंपों को जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई हैयाचिकाकर्ताओं को अचानक अपने आस-पास के प्रदूषण के बारे में क्यों पता चला है?

सरकार ने नई सुविधा की स्थापना को कब मंजूरी दी है?याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1996 में चंडीगढ़ सेक्टर 27 और 34 में पेट्रोल पंपों की स्थापना पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?याचिकाकर्ताओं ने पुरानी तकनीक का उपयोग करने वाले पेट्रोल पंपों को जारी रखने पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?वास्तव में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है।यह प्रतिवादी का निश्चित मामला है कि नई सुविधा नवीनतम तकनीक पर आधारित है।यह पर्यावरण के अनुकूल है।इसे पलटने की कोई बात नहीं है।यह दिखाने के लिए कोई डेटा नहीं दिया गया है कि दावा गलत है।इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(19) यह तर्क दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का दायित्व है।निस्संदेह ऐसा ही है।वास्तव में यह एक ऐसा दायित्व है जो न केवल राज्य के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए भी लागू होता है।हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रशासन पर्यावरण की रक्षा करने में विफल रहा है।

(20) इससे पहले वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में गैस स्टेशनों/पेट्रोल पंपों/ईंधन भरने वाले स्टेशनों को मंजूरी दी गई है।वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है।कुछ भी नया या असामान्य नहीं किया गया है।इसके अलावा, दोनों पेट्रोल पंपों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए?भारतीय सड़क कांग्रेस ने निस्संदेह सिफारिश की है कि यह 300 मीटर होना चाहिए।हालाँकि, यह केवल एक सिफारिश है।यह कानून का अनिवार्य प्रावधान नहीं है।एडमिन जे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने "सिफारिशों को नहीं अपनाया है।इस स्थिति में, उस पर विवादग्रस्त सुविधा की स्थापना के लिए स्थल को मंजूरी देने में अवैध रूप से कार्य करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

(21) याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि नई

सुविधा पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगी।यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि यह किसी भी प्रदूषण का कारण बन सकता है।याचिका में किए गए सामान्य और अस्पष्ट कथन सकारात्मक निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकते हैं।

(22) तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इकाई अस्वीकार्य प्रदूषण का कारण बनेगी ताकि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।

(23) अंत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि सेक्टर 21 में बनाए गए उद्यानों में कोई पेड़ नहीं लगाया गया है।नतीजतन, प्रतिवादी को पेड़ लगाने का निर्देश जारी किया जाए।

(24) याचिका में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है।हालाँकि, यदि याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई शिकायत है, तो प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यह इसके योग्य है।

याचिकाकर्ताओं की नेकनीयती:

(25) प्रतिवादी की ओर से, यह जोरदार तर्क दिया गया कि याचिका की गणना जनहित को बढ़ावा देने के लिए नहीं की गई है।क्या ऐसा ही है?

(26) श्री सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता नहीं चाहते कि घटिया इकाई को बंद कर दिया जाए।वे किसी अन्य पेट्रोल पंप की स्थापना पर आपत्ति नहीं करते हैं।उन्होंने पुरानी तकनीक का उपयोग करने वाले पंपों की निरंतरता के खिलाफ अपनी छोटी उंगली नहीं उठाई है।

(27) आधुनिक शहर चंडीगढ़ समृद्ध रूप से एक आधुनिक सुविधा का हकदार है।इस तरह की सुविधा की स्थापना को रोकने से जनहित को बढ़ावा नहीं मिलेगा।मामले की परिस्थितियों में, प्रतिवादी की ओर से यह सुझाव कि याचिका जनहित में नहीं है, बल्कि एक निजी हित याचिका है, पूरी तरह से निराधार नहीं कहा जा सकता है।हम और नहीं कहते हैं।

(28) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है।नतीजतन, इसे खारिज कर दिया जाता है।परिणामस्वरूप, 4 जनवरी, 1997 को पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश भी खाली हो जाएगा।यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी को लागत के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए था।हालाँकि, हम केवल इस उम्मीद के साथ ऐसा करने से बचते हैं कि याचिकाकर्ता भविष्य में एक बेहतर कारण का समर्थन करेंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)